



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिभक्त से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 1994/भाद्र 2, 1916
No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 1994/BHADRA 2, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 235 (पी एन) / 92-97

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

फाईल सं. एच. बी. / 5/113/92-97.—यथामंशोधित निर्यात एवं आयात नीति 1992-97 के पैरा 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च 1994) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अध्याय 4 में पैराग्राफ 22-क, निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“निर्यात संवर्धन आधार सुदृढ़ करने की दृष्टि से, लघु उद्योगों में भिन्न यूनितों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के संबंध में नई क्षमताओं को बढ़ाने या मंजूर करने की

अनुमति है, यदि वे तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर प्राप्त किए जाने वाले नए या अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75% नियति दायित्व पूरा करने का आश्वासन देते हैं और औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उद्योग लाइसेंस प्राप्त करते हैं। नियति दायित्व पूरा करने की निगरानी रखने का कार्य विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया जाएगा।”

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा पी. एल. सजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 235(PN)|92—97

New Delhi, the 24th August, 1994

File No. HB/5/113/92-97.—In exercise of the powers conferred under, Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures, 1992—97 (Revised Edition : March, 1994) :—

1. In Chapter IV, Paragraph 22-A shall be substituted by the following paragraph :—

“In order to strengthen the export promotion base, units other than small scale units are permitted to expand or create new capacities in respect of items reserved for the small scale sector, if they undertake an export obligation of a minimum of 75 per cent of the new or additional production to be achieved within a maximum period of 3 years and obtain an Industrial Licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 from Secretariat for Industrial Approvals. Discharge of the export obligation shall be monitored by the Directorate General of Foreign Trade.”

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade.